IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, RESEARCH JOURNAL
Vol. 1, Issue 01, Nov 2022

नई शिक्षा नीति 2020: देश के नव निर्माण में एक बदलाव की पहल

[1]डा0 अरविन्द कुमार शुक्ल
[1]सहायक प्रोफेसर– राजनीति विज्ञान, राजकीय महिला स्ना0 महाविद्यालय बिन्दकी, फतेहपुर (उ0प्र0)

Abstract

नई शिक्षा नीति में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम पुनः "शिक्षा मंत्रालय" करने का फैसला लिया गया है। इसमें समस्त उच्च शिक्षा (कानूनी एवं चिकित्सीय शिक्षा को छोड़कर) के लिए एक एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन करने का प्रावधान है। संगीत, खेल, योग आदि को सहायक पाठ्यक्रम या अतिरिक्त पाठ्यक्रम की बजाय मुख्य पाठ्यक्रम में ही जोड़ा जाएगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कोठारी आयोग (1964–1966) की सिफारिशों पे आधारित 1968 में पहली बार महत्त्वपूर्ण बदलाव वाला प्रस्ताव इन्दिरा गांधी के प्रधानमन्त्री काल में बिल पारित हुआ था।

Keywords:– नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, भारत का नव निर्माण, बदलाव की पहल, भारतीय संविधान, नीति निदेशक तत्व, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, शिक्षा मंत्रालय।

भूमिका

नई शिक्षा नीति बेरोजगार तैयार नहीं करेगी, स्कूल में ही बच्चे को नौकरी के जरूरी प्रोफेशनल शिक्षा दी जाएगीः कस्तूरीरंगन

अगस्त 1985 'शिक्षा की चुनौती' नामक एक दस्तावेज तैयार किया गया जिसमें भारत के विभिन्न वर्गों (बौद्धिक, सामाजिक, राजनैतिक, व्यावसायिक, प्रशासकीय आदि) ने अपनी शिक्षा सम्बन्धी टिप्पणियाँ दीं और 1986 में भारत सरकार ने 'नई शिक्षा नीति 1986' का प्रारूप तैयार किया। इस नीति की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इसमें सारे देश के लिए एक समान शैक्षिक ढाँचे को स्वीकार किया और अधिकांश राज्यों ने 10 + 2 + 3 की संरचना को अपनाया। इसे राजीव गांधी जी के प्रधानमन्त्रीत्व में जारी किया गया था।

इस नीति में 1992 में संशोधन किया गया था। 2014 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में एक नवीन शिक्षा नीति बनाने का विषय शामिल था। 2019 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति के लिये जनता से सलाह मांगना शुरू किया था।

परिकल्पना

1– नई शिक्षा नीति को भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी पहल है यह तेजी से बदलते हुए समय और जरूरतों के मुताबिक है। यह भारत के नवनिर्माण एवं देश की छवि सुधारने का सही समय एवं अवसर है।

2– नई शिक्षा नीति में बच्चों पर से बोर्ड परीक्षा का भार कम किया जाएगा तो उच्च शिक्षा के लिए भी अब सिर्फ एक नियामक होगा। पढ़ाई बीच में छूटने पर पहले की पढ़ाई बेकार नहीं होगी।

IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, RESEARCH JOURNAL
Vol. 1, Issue 01, Nov 2022

एक साल की पढ़ाई पूरी होने पर सर्टिफिकेट और दो साल की पढ़ाई पर डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाएगा।

3– नई शिक्षा नीति नए भारत का आधार है, यह छात्रों को समग्रता में जोड़ने वाली नीति है, हम सभी एक पारस्परिक निर्भर समाज में रह रहे है तथा सभी एक दूसरे से जुड़े है। इसलिए सरकार, सिविल सोसाइटी और समाज के विभिन्न वर्गो व शैक्षिक अभिकरणों को इस नीति का लक्ष्य पाने के लिए मिल जुलकर कार्य करना होगा।

4– नई शिक्षा नीति मे मल्टीपल डिस्प्लिनरी एजुकेशन की बात कही गई है। इसका मतलब यह है कि कोई भी छात्र विज्ञान के साथ–साथ कला और सामाजिक विज्ञान के विषयों को भी दसवीं–बारहवीं बोर्ड और ग्रेजुएशन में चुन सकता है। इसमें कोई एक स्ट्रीम मेजर और दूसरा माइनर होगा। कई छात्र ऐसे होते हैं जो विज्ञान के विषयों में रूचि के साथ–साथ संगीत या कला भी पढ़ना चाहते हैं। उनके लिए यह काफी फायदेमंद होगा। इसके अलावा विभिन्न शिक्षण संस्थान भी मल्टी डिस्पिलनरी होंगे इसका अर्थ यह है कि आईआईटी और आईआईएम में इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के अलावा अन्य विषयों को भी पढ़ाया जा सकेगा।

5– नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा के तहत ग्रेडेड अटॉनोमी की भी बात कही गई है, जिसमें विश्वविद्यालयों के ऊपर से बोझ को कम किया जाएगा और कॉलेजों को भी अकादमिक, प्रशासनिक और आर्थिक स्वायत्तता दी जाएगी। दरअसल इस ग्रेडेड अटॉनोमी के तहत नई शिक्षा नीति में प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान में एक प्रशासनिक ईकाई 'बोर्ड ऑफ गवर्नर' की बात की गई है, जिसके अन्तर्गत सभी अकादमिक, प्रशासनिक और आर्थिक शक्तियां आएंगी।

6– नई शिक्षा नीति मे ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर, नए सुधारों में टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर दिया गया है। कंप्यूटर, लैपटॉप और फोन इत्यादि के जरिए विभिन्न ऐप का इस्तेमाल करके शिक्षण को रोचक बनाने की बात कही गई है।

7– नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा के क्षेत्र में सुधार का एक महत्वपूर्ण रोडमैप है।

अध्ययन पद्धति

प्रस्तुत शोध पत्र में अनुसूची विधि और निरीक्षण प्रविधि का प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त अध्ययन संबंधी द्वितीय तथ्यों को विभिन्न शोध प्रबंधों, गजेटियर, शोध पत्रिकाओं एवं समाचार पत्रों से डेटा एकत्रित्र व प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया है। यह शोध–पत्र पुस्कालय अध्ययन पद्धति पर आधारित है।

करीब 34 साल बाद आई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं। बच्चों पर से बोर्ड परीक्षा का भार कम किया जाएगा तो उच्च शिक्षा के लिए भी अब सिर्फ एक नियामक होगा। पढ़ाई बीच में छूटने पर पहले की पढ़ाई बेकार नहीं होगी। एक साल की पढ़ाई पूरी होने पर सर्टिफिकेट और दो साल की पढ़ाई पर डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसमें 2030 तक प्री–प्राइमरी से लेकर उच्चतर माध्यमिक तक 100 फीसदी और उच्च

IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, RESEARCH JOURNAL
Vol. 1, Issue 01, Nov 2022

शिक्षा में 50 फीसदी प्रवेश दर हासिल करने की बात कही गई है। शिक्षा पर सरकारी खर्च 4.43 फीसदी से बढ़ाकर जीडीपी का छह फीसदी तक करने का लक्ष्य है।

अब स्कूल के पहले पांच साल में प्री–प्राइमरी स्कूल के तीन साल और कक्षा एक और कक्षा 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। इन पांच सालों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार होगा। अगले तीन साल का स्टेज कक्षा 3 से 5 तक का होगा। इसके बाद 3 साल का मिडिल स्टेज आएगा यानी कक्षा 6 से 8 तक का स्टेज। अब छठी से बच्चे को प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा दी जाएगी। स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। चौथा स्टेज (कक्षा 9 से 12वीं तक का) 4 साल का होगा। इसमें छात्रों को विषय चुनने की आजादी रहेगी। साइंस या गणित के साथ फैशन डिजाइनिंग भी पढ़ने की आजादी होगी। पहले कक्षा एक से 10 तक सामान्य पढ़ाई होती थी। कक्षा 11 से विषय चुन सकते थे।

अभी तक सरकारी स्कूल पहली कक्षा से शुरू होते हैं। लेकिन नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद पहले बच्चे को पांच साल के फाउंडेशन स्टेज से गुजरना होगा। फाउंडेशन स्टेज के आखिरी दो साल पहली कक्षा और दूसरी कक्षा के होंगे। पांच साल के फाउंडेशन स्टेज के बाद बच्चा तीसरी कक्षा में जाएगा। यानी सरकारी स्कूलों में तीसरी कक्षा से पहले बच्चों के लिए 5 लेवल और बनेंगे। 5 + 3 + 3 + 4 के नए स्कूल एजुकेशन सिस्टम में पहले पांच साल 3 से 8 साल के बच्चों के लिए, उसके बाद के तीन साल 8 से 11 साल के बच्चों के लिए, उसके बाद के तीन साल 11 से 14 साल के बच्चों के लिए और स्कूल में सबसे आखिर के 4 साल 14 से 18 साल के बच्चों के लिए निर्धारित किए गए हैं।

नई शिक्षा नीति को अंतिम रूप देने के लिए बनाई गई समिति का नेतृत्व कर रहे डॉ. कस्तूरीरंगन ने कहा, अब छठी कक्षा से ही बच्चे को प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा दी जाएगी। स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर जोर दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति बेरोजगार तैयार नहीं करेगी। स्कूल में ही बच्चे को नौकरी के जरूरी प्रोफेशनल शिक्षा दी जाएगी।

दसवीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में बड़े बदलाव किए जाएंगे। बोर्ड परीक्षाओं के महत्व को कम किया जाएगा। कई अहम सुझाव हैं। जैसे साल में दो बार परीक्षाएं कराना, दो हिस्सों वस्तुनिष्ठ (ऑब्जेक्टिव) और व्याख्यात्मक श्रेणियों में इन्हें विभाजित करना आदि। बोर्ड परीक्षा में मुख्य जोर ज्ञान के परीक्षण पर होगा ताकि छात्रों में रटने की प्रवृत्ति खत्म हो। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर छात्र हमेशा दबाव में रहते हैं और ज्यादा अंक लाने के चक्कर में कोचिंग पर निर्भर हो जाते हैं। लेकिन भविष्य में उन्हें इससे मुक्ति मिल सकती है। शिक्षा नीति में कहा गया है कि विभिन्न बोर्ड आने वाले समय में बोर्ड परीक्षाओं के प्रैक्टिकल मॉडल को तैयार करेंगे। जैसे वार्षिक, सेमिस्टर और मोड्यूलर बोर्ड परीक्षाएं। नई नीति के तहत कक्षा तीन, पांच एवं आठवीं में भी परीक्षाएं होगीं। जबकि 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं बदले स्वरूप में जारी रहेंगी। नई शिक्षा नीति में पांचवीं तक और जहां तक संभव हो सके, आठवीं तक मातृभाषा में ही शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी।

IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, RESEARCH JOURNAL
Vol. 1, Issue 01, Nov 2022

बच्चों की रिपोर्ट कार्ड में बदलाव होगा। उनका तीन स्तर पर आकलन किया जाएग। एक स्वयं छात्र करेगा, दूसरा सहपाठी और तीसरा उसका शिक्षक। नेशनल एसेसमेंट सेंटर–परख बनाया जाएगा जो बच्चों के सीखने की क्षमता का समय–समय पर परीक्षण करेगा। सौ फीसदी नामांकन के जरिए पढ़ाई छोड़ चुके करीब दो करोड़ बच्चों को फिर दाखिला दिलाया जाएगा।

नीति में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट (बहु स्तरीय प्रवेश एवं निकासी) व्यवस्था लागू किया गया है। आज की व्यवस्था में अगर चार साल इंजीनियरंग पढ़ने या छह सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश आगे नहीं पढ़ पाते हैं तो कोई उपाय नहीं होता, लेकिन मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में एक साल के बाद सर्टिफिकेट, दो साल के बाद डिप्लोमा और 3–4 साल के बाद डिग्री मिल जाएगी। यह छात्रों के हित में एक बड़ा फैसला है। 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है और शोध में नहीं जाना है। वहीं शोध में जाने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी। 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट्स एक साल में ड। कर सकेंगे। नई शिक्षा नीति के मुताबिक यदि कोई छात्र इंजीनियरिंग कोर्स को 2 वर्ष में ही छोड़ देता है तो उसे डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। इससे इंजीनियरिंग छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी। पांच साल का संयुक्त ग्रेजुएट–मास्टर कोर्स लाया जाएगा। एमफिल को खत्म किया जाएगा और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में एक साल के बाद पढ़ाई छोड़ने का विकल्प होगा। नेशनल मेंटरिंग प्लान के जरिये शिक्षकों का उन्नयन किया जाएगा।

बीएड 4 साल का होगा। 4 वर्षीय बीएड डिग्री 2030 से शिक्षक बनने की न्यूनतम योग्यता होगी। नीति के अनुसार, पेशेवर मानकों की समीक्षा एवं संशोधन 2030 में होगा और इसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष में होगा। शिक्षकों को प्रभावकारी एवं पारदर्शी प्रक्रियाओं के जरिए भर्ती किया जाएगा। पदोन्नति योग्यता आधारित होगी। कई स्रोतों से समय–समय पर कार्य–प्रदर्शन का आकलन किया जाएगा।

यूजीसी एआईसीटीई का युग खत्म हो गया है। उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने बताया कि उच्च शिक्षा में यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई की जगह एक नियामक होगा। कॉलेजों को स्वायत्ता (ग्रेडेड ओटोनामी) देकर 15 साल में विश्वविद्यालयों से संबद्धता की प्रक्रिया को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का ऑफर दिया जाएगा। यह संस्थान के लिए अनिवार्य नहीं होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यह परीक्षा कराएगी। स्कूल शिक्षा सचिव अनीता करवाल ने बताया कि स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा में दस–दस बड़े सुधारों पर मुहर लगाई गई है।

नई नीति में तकनीक के इस्तेमाल पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्री–प्राइमरी शिक्षा के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। इसके तहत तीन से छह वर्ष तक की आयु के बच्चे आएंगे। 2025 तक कक्षा तीन तक के छात्रों को मूलभूत साक्षरता तथा अंकज्ञान सुनिश्चित किया जाएगा। मिडिल कक्षाओं की पढ़ाई पूरी तरह बदल जाएगी। कक्षा छह से आठ के बीच विषयों की पढ़ाई होगी। उच्च शिक्षण संस्थानों को ऑनलाइन स्वतः घोषणा के आधार पर मंजूरी मिलेगी। मौजूदा इंस्पेक्टर राज खत्म होगा। अभी केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, डीम्ड

IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, RESEARCH JOURNAL
Vol. 1, Issue 01, Nov 2022

विश्वविद्यालय और प्राइवेट विश्वविद्यालय के लिए अलग–अलग नियम हैं। भविष्य में सभी नियम एक समान बनाए जाएंगे। फीस पर नियंत्रण का भी एक तंत्र तैयार किया जाएगा।

सभी तरह के वैज्ञानिक एवं सामाजिक अनुसंधानों को नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाकर नियंत्रित किया जाएगा। उच्च शिक्षण संस्थानों को बहु विषयक संस्थानों में बदला जाएगा। 2030 तक हर जिले में या उसके आसपास एक उच्च शिक्षण संस्थान होगा। शिक्षा में तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। इनमें आनलाइन शिक्षा का क्षेत्रीय भाषाओं में कंटेट तैयार करना, वर्चुअल लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, स्कूलों, शिक्षकों और छात्रों को डिजिट संसाधनों से लैस कराने जैसी योजनाएं शामिल हैं। स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा के साथ कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसी व्यावसायिक शिक्षा भी नई शिक्षा नीति के दायरे में होगा।

कला, संगीत, शिल्प, खेल, योग, सामुदायिक सेवा जैसे सभी विषयों को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इन्हें सहायक पाठ्यक्रम नहीं कहा जाएगा। नए सुधारों में टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर दिया गया है। कंप्यूटर, लैपटॉप और फोन इत्यादि के जरिए विभिन्न ऐप का इस्तेमाल करके शिक्षण को रोचक बनाने की बात कही गई है। हर जिले में कला, करियर और खेल–संबंधी गतिविधियों में भाग लेने के लिए एक विशेष बोर्डिंग स्कूल के रूप में 'बाल भवन' स्थापित किया जाएगा।

निष्कर्ष एवं सुझाव–

- नई शिक्षा नीति 2020 पर के विभिन्न पहलुओं पर विचार करनें पर स्पष्ट होता है कि राश्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: भारत के नव निर्माण में एक बदलाव की पहल से संबन्धित कतिपय महत्वपूर्ण बिन्दू निम्नवत हैं।
  - न्यूनतम छात्र संख्या पर भी जितने विषय हो कम से कम उतने शिक्षक नियुक्त करना आवश्यक। पहले भवन फिर पद सृजन फिर शिक्षक नियुक्ति तदनुपरांत ही नवीन विद्यालय खोलने अथवा क्रमोनत करने का प्रावधान हो।
  - निजी विद्यालयों की शैक्षणिक गुणवत्ता की भी नियमित जांच हो। वहां के विद्याथियों –शिक्षको के अधिकारो के हनन पर सख्त कानून बने।
  - शिक्षा की गुणवत्ता का कागज पर जांच बन्द हो। सक्रिय शिक्षण को बल दिया जाए। अनुशासन पर दण्ड हो, शिक्षण पर दण्ड प्रतिबंधित रहे।
  - निजी विद्यालय और सरकारी विद्यालय में प्रवेश आयु समान हो, विविध कारणों से शिक्षण न करा पाने वाले शिक्षको को अच्छे पैकज के साथ एवं अयोग्यता अथवा लापरवाही करने वालो को समान्य पैकज से तुन्त सेवानिर्वत करने का प्रावधान हो।
  - शिक्षा संलग्न कार्य दोयम दर्जे के, शिक्षण कार्य प्राथमिक दर्जे का माना जाये। विद्यालय भवन, पानी, बिजली, पंखा, शौचालय एवं स्वीपर अवश्य हो।
  - कोविड–19 के कारण उत्पन्न परिस्थिति, भारतीय समाज में पाश्चात्य संस्कृति के बढ़ते प्रभावों और सामाजिक, आर्थिक तकनीकि में तेज गति से लगातार हो रहे परिवर्तनों के

IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, RESEARCH JOURNAL
Vol. 1, Issue 01, Nov 2022

कारण शिक्षा नीति में समय के साथ सुधार की आवश्यकता कई वर्षो से महसूस की जा रही थी। इस नीति को उपयुक्त समय पर लाया गया है।

- यह लचीला होने के साथ–साथ इंटीग्रेटेड, समाज के सभी वर्गो को जोडने वाला सामाजिक आर्थिक बदलाव और भारत को ज्ञान–विज्ञान के शिखर पर पहुँचाने और संस्कृति–सभ्यता का खोई हुयी गौरव की पुर्नस्थापना करने के लिये दिशा प्रदान करता है।
- शिक्षा में बहुविषयक प्रणाली लागू होने से छात्रों की अध्ययन में रूचि बढ़ेगी और बुद्धि कुशाग्र होगी।
- आर्थिक और अन्य कारणों से बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले का नुकसान नही होगा और उन्हे प्रमाण–पत्र भी मिलेगा।
- इसके क्रियान्वयन हेतु प्रमुखतः ग्रामीण क्षेत्रों में संरचनात्मक विकास बिजली, सड़क, इंटरनेट आदि की गति को तीव्र करने की आवश्यकता है।
- छात्रों और शिक्षकों को तकनीकि अपनाने हेतु प्रेरित करने और अवसर सुविधाएँ प्रदान करने की आवश्यकता है इसके लिए कम्प्यूटर में ट्रेनिग प्रदान करने और लैब की संख्या गांव गांव में बढ़ाई जाने चाहिए।

संदर्भ :–

1. (2020) – नई शिक्षा नीति : प्रमुख प्वाइन्ट्स : एक नजर में, 30 जुलाई।
2. (2020) – नई शिक्षा नीति : पढ़ाई, परीक्षा, रिपोर्ट कार्ड, 'आज तक' 30 जुलाई।
3- (2020) – https://m.jagaran.com > editorial > ap - National educational policy. 17 August.
4- www.Jagran.com
5- www.amarujala.com